कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगी

हेल्थ, एजुकेशन को प्राथमिकता

बजट 2026-27

टैक्स, हेल्थ, रक्षा और महिलाओं पर फोकस

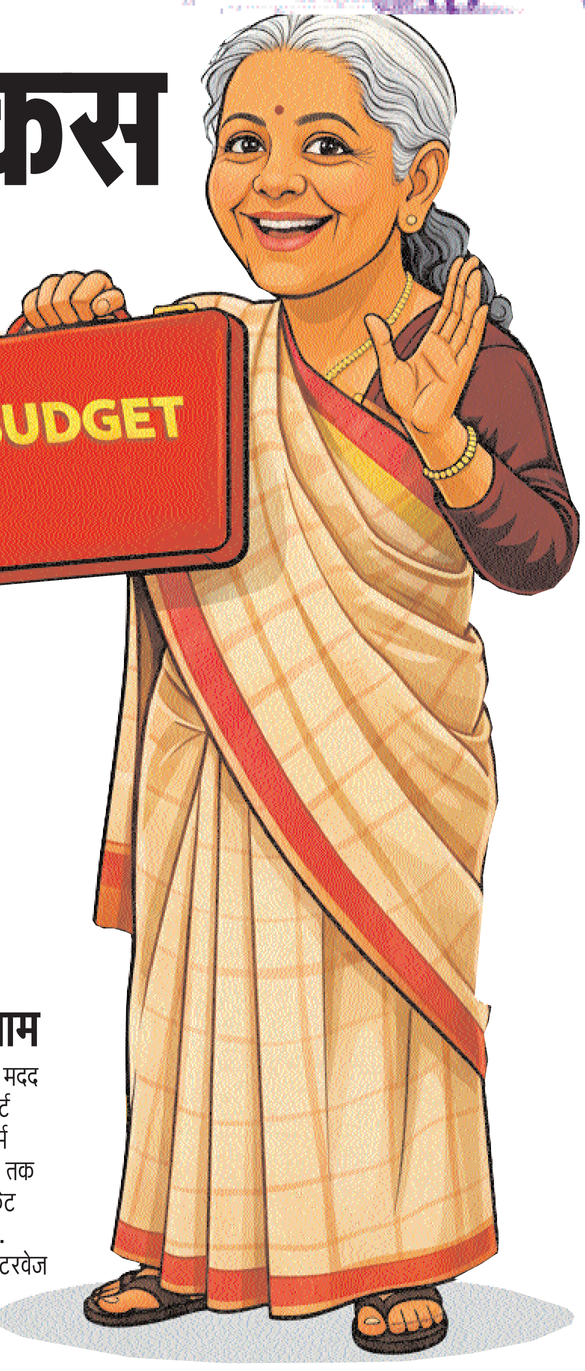

नई दिल्ली, 1 फरवरी. बजट में इस बार आम आदमी की जरूरतों से जुड़े सेक्टर पर बड़ा जोर दिखा. हेल्थकेयर में दवाओं पर ड्यूटी छूट, एजुकेशन में कंटेंट क्रिएटर लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, किसानों के लाभ जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

सरकार ने साफ संकेत दिया कि विकास की रफ्तार, लोगों की क्षमता और हर क्षेत्र की भागीदारी—इन तीन विजन पर आगे बढ़ा जाएगा. साथ ही टैक्स स्लैब स्थिर रखते हुए रिवाइज्ड रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई. वित्त मंत्री ने बजट में 7 बड़ी घोषणाएं करते हुए हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी. कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया गया. 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगी, जबकि 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे. 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा से कनेक्टिविटी मजबूत होगी. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर 12.2 लाख करोड़ खर्च होंगे. टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक भर सकेंगे. मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 मेडिकल हब और 3 आयुर्वेदिक एआईआईएमएस भी खुलेंगे.

पांच साल में 20 नए राष्ट्रीय बनेंगे जलमार्ग

रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर- 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे. अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे. बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख खर्च होंगे

डिफेंस बजट के लिए 7.85 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले 15.2प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. कुल रकम में से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख खर्च होंगे. पिछले साल यह 1.80 लाख करोड़ था. विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं. पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं. बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया.

एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता- पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटी

नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है. डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर अब टैक्स नहीं देना होगा.

आयुर्वेद- भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का ऐलान किया गया है. आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी. भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा.

गर्ल्स एजुकेशन- करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल देश में 789 जिले हैं. हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है. गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही.

महिलाएं- लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए एसएचई -मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे. इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे. यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे. इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा.

बजट की उत्पत्ति से लेकर इतिहास तक...

चमड़े के झोले से 'बजट'

'बजट' शब्द सुनते ही दिमाग में आय-व्यय, टैक्स और सरकारी योजनाओं की तस्वीर उभरती है. लेकिन इसकी जड़ें एक छोटे से चमड़े के थैले से जुड़ी हैं. फ्रेंच शब्द ' बोगेटे' से निकला यह शब्द लैटिन ' बुल्गा' और सेल्टिक 'ब्लोग से भी संबंध रखता है. समय के साथ यह थैला सिर्फ सामान रखने का साधन नहीं रहा, बल्कि सरकारी लेखा-जोखा और वित्तीय पारदर्शिता का प्रतीक बन गया. यहीं से 'बजट' का आधुनिक अर्थ आकार लेने लगा. 17वीं-18वीं सदी के इंग्लैंड में वित्त मंत्री जरूरी दस्तावेज चमड़े के बैग में रखकर संसद जाते थे.

1860 में पेश हुआ था

देश का पहला यूनियन बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया. उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था. यह बजट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने पेश किया था. 1857 की क्रांति के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी. उसी घाटे को संभालने और सरकारी खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए पहली बार बजट का कॉन्सेप्ट लाया गया. यहीं से भारत में सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है. बता दें भारत के बजट इतिहास का सबसे लंबा भाषण 2020 में देखने को मिला था. यह भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने दिया, जो 2 घंटे 40 मिनट तक चला. लगातार पढ़ते-पढ़ते उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भाषण बीच में रोकना पड़ा. इसके बाद बाकी हिस्सा संसद में लिखित रूप में पेश किया गया.

सबसे छोटा बजट भाषण

जहां एक तरफ लंबा भाषण रिकॉर्ड बना. वहीं, भारत ने बेहद छोटा बजट भाषणा भी देखा. 1977 में मोरारजी देसाई की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हीरूभाई मुल्जीभाई पटेल ने सिर्फ 800 शब्दों में बजट भाषण खत्म कर दिया था. यह आज तक का सबसे छोटा और संक्षिप्त बजट भाषण माना जाता है.

रेल बजट अलग होता था

भारत में रेल बजट पहले अलग से पेश किया जाता था. 1924 से 2016 तक रेलवे का बजट यूनियन बजट से अलग ही रहा. 2017 में मोदी सरकार ने इसे केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉलिसी लागू करने की प्रोसेस आसान हो सके. रेल बजट में सैकड़ों नई ट्रेनों की घोषणा की जाती थी. इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट का विस्तार भी किया जाता था. वहीं 1950 तक बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में हुआ करती थी, लेकिन उसी साल बजट लीक की घटना ने यह प्रक्रिया बदल गई. इस लीक के कारण तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा. इसके बाद सरकार ने प्रिंटिंग मिंटो रोड प्रेस और बाद में नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में शिफ्ट कर दी.

आयकर की शुरुआत

ब्रिटिश इंडिया के पहले बजट से ही आयकर की शुरुआत हो गई थी. यानी 1860 में इस सिस्टम को लाया गया. इसे शुरुआत में अस्थायी व्यवस्था माना गया, लेकिन धीरे-धीरे यह सरकार की इनकम का परमानेंट पिलर बन गया. इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पर है. उन्होंने अलग-अलग कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किए.

इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे

1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे. सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है. इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे. हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए - इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे.

लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम

एमएसएमई के लिए- सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी. लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा. साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा. ट्रेड से लिंक करेंगे. एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे. प्रोफेशनल सपोर्ट - शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं. टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी. रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है. कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा. पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है. वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग - वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा.

खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा. वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. स्पोर्ट्स - उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है. इंडस्ट्रियल क्लस्टर - इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है.

मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट

भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके.

यहां से लाया जाएगा रुपया

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में आमंदनी और खर्च का ब्योरा एक रुपये के आधार पर इस प्रकार है.

- **18** प्रतिशत निगम कर से लाया जाएगा रुपया
- **10** प्रतिशत गैर कर राजस्व से और गैर ऋण पूंजी प्राप्ति से 2 प्रतिशत
- **06** प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राशि लाने की तैयारी
- **15** प्रतिशत जीएसटी और अन्य करों से जुटाई जाएगी राशि
- **07** प्रतिशत वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण भी किया जाएगा

- **20** प्रतिशत ऋण भुगतान
- **06** प्रतिशत प्रमुख सब्सिडी
- **11** प्रतिशत रक्षा के लिए
- **02** प्रतिशत सिविल पेंशन
- **17** फीसदी केन्द्रीय योजना
- **07** फीसदी अन्य व्यय

सरकार की कमाई, कर्ज और घाटे का पूरा हिसाब

सरकारी कर्ज में कमी लाने का लक्ष्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030-31 तक देश का कुल कर्ज, जीडीपी के 50 प्रतिशत के बराबर लाया जाए. 2025-26 में यह कर्ज 56.1 फीसदी था, जो अब 2026-27 में घटकर 55.6 फीसदी रहने का अनुमान है. यह कर्ज कम होगा तो सरकार को ब्याज कम देना पड़ेगा, जिससे वो पैसा स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च हो सकेगा. राजकोषीय घाटा पिछली बार से कम हुआ राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर. सरकार ने कहा है कि वह घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे ले आई है. 2025-26 में यह घाटा 4.4 फीसदी रहा। अगले साल (2026-27) के लिए इसे और घटाकर 4.3 फीसदी करने का लक्ष्य है. पिछले साल (2025-26) का हिसाब किताब सरकार की कुल कमाई 34 लाख करोड़ रही. इसमें से 26.7 लाख करोड़ टैक्स से आए. वहीं कुल खर्च 49.6 लाख करोड़ रहा. पूंजीगत खर्च यानी लगभग 11 लाख करोड़ नए ब्रिज, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च हुआ. अगले साल (2026-27) का बजट प्लान सरकार ने 36.5 लाख करोड़ कुल कमाई का अनुमान है.

- टैक्स अनुमान - 34 लाख करोड़ का है.
- कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ व बजट एस्टीमेट 36.5 लाख करोड़ का है.
- न्यू इनकम टैक्स एक्ट आगामी एक अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा.
- सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए हैं, आम आदमी भर सके.

- कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी रखने का लक्ष्य - 2031 तक हासिल करेंगे.
- हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा
- 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे. केयर गिवर्स को ट्रेनिंग
- एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 2 प्रतिशत टैक्स किया है.
- युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने स्कीम लाएंगे
- मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी है.
- ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत टैक्स किया गया है.
- एम्पलॉइज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 फीसदी टैक्स होगा.
- राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य

पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट

पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे. मेडिकल टूरिज्म - भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव. वहीं 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं.

ट्रॉमा केयर सेंटर

पूर्वोदय स्कीम - पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट - अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा. राज्यों को मदद - 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गई.

मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे

नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर, नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी.

एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी. मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे

पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रिया

हॉस्टल-इंफ्रा पर सियासी बयानबाजी, बजट बना विकास बनाम सवालों का मुद्दा

केंद्रीय बजट पेश होते ही सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया. केंद्रीय बजट को लेकर नेताओं का अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आ रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक आधारित हॉस्टलों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर को युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला बताया. ब्रजेश पाठक, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शिवराज सिंह चौहान ने इसे विकसित भारत, सुशासन, स्वास्थ्य और कृषि सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम कहा. वहीं, सांसद शशि थरूर ने कहा - बिना नौकरी के ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है - अखिलेश यादव ने शेयर बाजार गिरावट का हवाला देते हुए बजट को सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के हित वाला बताया.

जनभावनाओं वाला बजट

राजनाथ सिंह

रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित होने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है.

लोक-कल्याण वाला बजट

जेपी नड्डा

इस बार का पेश किया बजट को लोक-कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति संकल्पित देश के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक है.

बजट सुशासन व विकसित

नितिन नबीन

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर्तव्य भवन में बना और कर्तव्य पथ पर चलने वाला बजट है. यह देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी, दूरदर्शिता और जनकल्याणकारी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.

आकांक्षाओं को पूरा किया

योगी आदित्यनाथ

देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि, रेल कॉरिडोर, जैसे ठोस प्रावधान किए गए हैं.

विकास पर केंद्रित बजट

किरेन रिजिजू

बजट में कोई राजनीतिक बात नहीं कही गयी, यह पूरी तरह विकास पर केंद्रित है. विकसित भारत के लिए पीएम ने जो 'रिफार्म एक्सप्रेस' चलाया गया है, उसी की झलक इसमें है।

बजट पांच प्रतिशत के लिए

अखिलेश यादव

भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से भी क्या अपेक्षा की जा सकती है. हर बजट 1/20 का बजट होता है, क्योंकि यह केवल 5 प्रतिशत लोगों के हित के लिए होता है.

बिना नौकरी के ग्रोथ नहीं

शशि थरूर

बिना नौकरी के ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है. हम इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि वित्त मंत्री किस तरह की स्कीम्स लाती हैं, जिससे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी.

संकल्पों की सिद्धि का बजट

ब्रजेश पाठक

यह बजट करोड़ों देशवासियों की आशाओं, और संकल्पों की सिद्धि का बजट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को मजबूती प्रदान करेगा.